quality planting material to the orchardist, a total of 85 large conventional nurseries in public sector, 587 small nurseries and 37 tissue culture units in public and private sector are also included. Fund has also been allocated for field demonstration training of farmers and publicity materials on improved fruit production technology. National Horticulture Board (NHB) is also giving assistance to the extent of Rs. 50,000/- per group of 50 farmers for training. Besides, 10 fruit plants at a maximum cost of Rs. 50/- per family is being distributed freely by NBH for the establishment of nutritional garden in rural areas.

Apart from these, Ministry of Rural Development have also launched a scheme on employment assurance for plantation of new fruit crops, for those who are below poverty line under which maximum assistance is available upto Rs. 15,000 per ha.

कपास के बीजों का वितरण

6577. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:**
श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में किसानों को वर्ष-वार कुल कितनी मात्रा में कपास के बीजों का वितरण किया गया ;

(ख) राज्य में उगाए जा रहे कपास की विभिन्न किस्मों के ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 1991–92 से 1993–94 तक के दौरान वितरित किये गए कपास के बीजों की मात्रा क्रमश: 0.61 लाख क्विंटल, 0.83 लाख क्विंटल तथा 0.89 लाख क्विंटल है।

(ख) राज्य में उगाई जा रही कपास की प्रमुख किस्में हैं–दिग्विजय, वी–797, संजय, रविराज, गुजरात–10, क्यू०यू०जे०–11, जी०यू०जे०–12, जी०यू० जे०–13, जी०यू०जे०–15, एल०आर०ए०–5166, एच–4, एच–6, एच–7, एच–8, एच–9, वरलक्ष्मी, डी०सी०एच०–32, इत्यादि।

(ग) 1991–92 से 1993–94 के दौरान क्रमश: 11.81 लाख, 19.89 लाख और 16.23 लाख गांठों का उत्पादन हुआ।

Central Research Institute for Jute and Alied Fibres

6578. SHRI MD. SALIM:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is fact that the Chief Minister of West Bengal has written to the Minister two letters on 13th September, 1994 and 6th December, 1994 proposing solutions for evolution of joint monitoring process involving the Central and State Government to sort out the problems concerning the Central Research Institute for Jute and Allied Fibres (CRIJAF), Barrackpore;

(b) if so, the response of Government to this proposal and the action taken in the matter; and

(c) if no action is proposed on the suggestions of the Chief Minister, how Government propose to enable the institute to play a meaningful role in the development of jute industry—a major industry in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) It is proposed to hold a ministerial level meeting with the Chief Minister, West Bengal after the Budget Session of the Parliament.

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों हेतु अप्रयुक्त भूमि

6579. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 मार्च, 1995 के "दि आब्जर्वर" में "पंचम सेक्टर में वी ओपन्ड अप" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार देश में पड़ी अप्रयुक्त सरकारी भूमि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों अथवा बड़े वित्तीय संस्थानों को कृषि के प्रयोजन हेतु देने पर विचार कर रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध इस प्रकार की भूमि की पहचान कर ली है, और

(ङ) यदि हां, तो देश में पड़ी ऐसी अप्रयुक्त भूमि के क्षेत्रफल का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऐसा प्रतीत होता है कि यह समाचार राष्ट्रीय संदर्भ योजना तैयार करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा परिचालित एक नोट पर आधारित है। ये केवल सुझाव हैं। चूंकि "भूमि कानून" राज्य सरकारों का विषय है, यह राज्य सरकारों का काम है कि वे भूमि के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के बारे में निर्णय लें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि

6580. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में दुग्ध उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है।

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1994-95 के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन कितना रहा ;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में दुग्ध दुधारू पशुओं की संख्या के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उनकी अनुमानित संख्या क्या है ;

(ङ) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक दुधारू पशु द्वारा दिए जाने वाले दूध की मात्रा भी बढ़ी है ;

(च) यदि हां, तो इस वृद्धि की दर क्या है तथा देश में इस समय अर्थात् वर्ष 1994-95 में प्रत्येक पशु द्वारा औसतन किस दर से दूध दिया जाता है; और

(छ) सरकार द्वारा प्रत्येक दुधारू पशु की उत्पादन दर को 1997 के अंत तक औसतन कितना करने का लक्ष्य है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) जी, हां। 1990-91 तथा 1994-95 के दौरान (अनन्तिम) अनुमानित दुग्ध उत्पादन क्रमशः 53.9 तथा 69.1 मिलियन मीटरी टन था।